

## केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र



श्री कुशविंदर वोहरा  
अध्यक्ष, के ज आ

### संदेश

पिछले महीने के दौरान, के.ज.आ. ने नई परियोजनाओं, प्रशिक्षण, अन्य देशों के साथ संबंध, जीएलओएफ से संबंधित गतिविधियों और अन्य तकनीकी अध्ययनों के लिए परामर्श के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।

के.ज.आ. ने दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए: पहला समझौता तापी नदी पर एक पारंपरिक बैराज के निर्माण में डिजाइन परामर्श प्रदान करने के लिए सूरत नगर निगम (एसएमसी, गुजरात) के साथ किया गया था। दूसरा समझौता ज्ञापन उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (यूपीडीसीसी) लिमिटेड, उत्तराखंड के साथ जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए समीक्षा डिजाइन परामर्श कार्य प्रदान करने हेतु किया गया था। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गोला नदी पर 150.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है।

हमने इस महीने भारत-जापान उप समूह/संयुक्त कार्यान्वयन समूह (जेआईजी) की दूसरी और तीसरी

बैठक भी की। भारत और जापान ने दिसंबर 2019 में जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एक संयुक्त कार्य समूह ((जेडब्ल्यूजी)) का गठन किया गया।

2016 में, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत, 99 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरणों) को कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया था। कुल 99 में से 58 परियोजनाएं (चरणों सहित) पूरी होने की सूचना है और 48 (चरणों सहित) अभी भी चल रही हैं। मेरी अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला में इन परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। समिति ने परियोजनाओं के मुद्दों/बाधाओं, पूरा होने की संभावित समय अवधि और चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के उपायों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इससे उनकी निधिकरण को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

हिमनद झील विस्फोट से उत्पन्न बाढ़ (जीएलओएफ) ग्लेशियरों और उच्च ऊंचाई वाली झीलों वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण और बढ़ता खतरा पैदा करता है। वर्तमान में के.ज.आ. हिमनदी झीलों/जल निकायों (जीएल/डब्ल्यूबी) की निगरानी कर रहा है। माह के दौरान हिमनद झील निगरानी (जीएलएम) और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) की भूमिका पर एक विज्ञान दस्तावेज़ तैयार किया गया

था। इस क्षेत्र में के.ज.आ.की भूमिका और चरणबद्ध तरीके से किए जाने वाले कार्यों की पहचान की गई है। जून, 2025 तक लगभग 2400 जीएल की निगरानी करने का प्रस्ताव है। यह इस क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के प्रयासों का पूरक होगा।

के.ज.आ. अधिकारियों के पांचवें और छठे बैच के लिए एक व्यापक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 28.05.2024 को राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), पुणे में "जल-गुणवत्ता डेटा की गुणवत्ता के विश्लेषण" पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू हुआ। प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य के.ज.आ. के इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक दोनों संवर्गों के अधिकारियों को गुणवत्ता पहलुओं के संबंध में आवश्यक अंतर्दृष्टि से लैस करना था।

केंद्रीय जल आयोग के 4 अधिकारियों की एक टीम ने ट्रॉयज़, फ्रांस में 2024 एडीसीपी रेगाटा में भाग लिया। यह कार्यक्रम ध्वनिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर (एडीसीपी) और अन्य डिस्चार्ज माप तकनीकों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आयोजित किया गया था। भारतीय टीम ने 1सोनटेक एम9 एडीसीपी; एक कप टाइप (वर्टिकल एक्सिस) करंट मीटर और एक पिग्मी करंट मीटर की मदद से अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया।

के.ज.आ. द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 20.05.2024 को व्याख्यान/प्रस्तुति सत्र के बाद एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की गई थी। फोर्टिस एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के हृदय रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक व्याख्यान दिया गया। प्रबंधक, एसबीआई द्वारा वित्तीय प्रबंधन पर और एसबीआई के साइबर विशेषज्ञ द्वारा साइबर जागरूकता पर प्रस्तुतियाँ भी दी गईं।

पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने हेतु संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने हेतु समिति की 5वीं बैठक भी मेरी अध्यक्षता में आयोजित की गई। मॉडल के आउटपुट की समीक्षा की गई और बैंक क्षरण के मुद्दों के समाधान के लिए आगे बढ़ने के संबंध में निर्णय लिए गए।

के.ज.आ. कई अन्य महत्वपूर्ण अध्ययनों पर काम कर रही है, जिनके जुलाई-अगस्त, 2024 तक पूरा होने की संभावना है जो जल क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए सहायक होंगे।

9/24

## विषयसूची

### विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

- ओकेआई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (जापान) के साथ बैठक
- भारत-जापान उपसमूह/संयुक्त कार्यान्वयन समूह (जेआईजी) की दूसरी और तीसरी बैठक

### परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

### साइटों/परियोजनाओं का दौरा

- खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स टेलिंग बांध, खेतड़ी, राजस्थान

### प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

- गोदावरी और तापी नदी घाटियों के लिए स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली
- ट्रॉयज़, फ्रांस में एडीसीपी रेगाटा

### अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

#### i. बाढ़ से संबंधित मामले

- देश में बाढ़ की स्थिति - मई 2024
- 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की तीसरी बैठक

#### ii. अंतर-राज्य विवाद

- पेन्नैयार नदी जल विवाद

#### iii. अन्य गतिविधियाँ

- केंद्रीय जल आयोग एवं सूरत नगर निगम तथा उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन
- भूकंपीय डिजाइन मापदंडों के मूल्यांकन के लिए के.ज.आ के एनसीएसडीपी दिशानिर्देशों में संशोधन

- गंगा-पद्मा नदी से उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए गठित समिति की पांचवीं बैठक
- विश्व बैंक द्वारा समर्थित सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की प्रगति पर चर्चा
- जल निकाय प्रबोधन ऐप
- आईसीआईडी की दीर्घकालिक वित्तीय और तकनीकी स्थिरता पर कार्यबल की दूसरी बैठक
- हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मजबूत करना (एससीए-हिमालय)-ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग फ्रेमवर्क का मसौदा

#### iv. जलाशय निगरानी

#### गैलरी

## विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

### ओकेआई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (जापान) के साथ बैठक



श्री केई काटो के नेतृत्व में ओकेआई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (जापान) के प्रतिनिधि, जो विभिन्न संचार उपकरणों और स्वचालित स्तर रिकॉर्डर से संबद्ध हैं, ने 10.05.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की। बैठक में के.ज.आ. (मुख्यालय), नई दिल्ली के अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

ओकेआई प्रतिनिधियों ने जल स्तर की निगरानी और ग्राउंड मूवमेंट सेंसर से संबंधित अपने समाधान प्रस्तुत किए। अध्यक्ष, के.ज.आ ने के.ज.आ द्वारा हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन और डेटा संग्रह प्रणालियों में उपयोग की जा रही तकनीक के बारे में भी बताया। इसके बाद इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श और चर्चाएं हुईं।

### भारत-जापान उपसमूह/संयुक्त कार्यान्वयन समूह (जेआईजी) की दूसरी और तीसरी बैठक

दिसंबर 2019 में, भारत और जापान ने जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे नियमित बातचीत के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) और एक उप समूह का गठन हुआ। भारत-जापान उप समूह/संयुक्त कार्यान्वयन समूह (जेआईजी) की दूसरी और तीसरी बैठकें क्रमशः 15 मई और 27 मई, 2024 को आभासी रूप से आयोजित की गईं।

भारतीय पक्ष द्वारा आयोजित दूसरी बैठक का नेतृत्व श्री पद्मा दोर्जे, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ), जल संसाधन विभाग (जल संसाधन विभाग), जल शक्ति मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय) ने किया। बैठक में दोनों देशों के जेआईजी सदस्यों



## विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

ने भाग लिया। जापानी पक्ष का नेतृत्व उप समूह के नोडल अधिकारी और जेडब्ल्यूजी के सदस्य सचिव श्री ताकाहिरो कोनामी ने किया।

27 मई, 2024 को आयोजित तीसरी बैठक, "भूमि धंसाव और जवाबी उपाय" पर केंद्रित थी। बैठक के दौरान, भारतीय पक्ष ने तीन शहरों: मोहाली-चंडीगढ़, दिल्ली-गुरुग्राम (एनसीआर), और मेहसाणा (गुजरात) में भूमि धंसाव मूल्यांकन अध्ययन के साथ भारत के अनुभव पर एक प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के सदस्य (मुख्यालय) श्री सतीश कुमार द्वारा दी गई, जो जेआईजी के भी सदस्य हैं।

जापानी पक्ष ने टोक्यो में भूमि धंसाव के कारण और उसे रोकने के उपायों सहित अपने अनुभव प्रस्तुत किये। उन्होंने टोक्यो में जापान की भूजल निगरानी व्यवस्था और 1956 के औद्योगिक जल उपयोग कानून और 1962 के भवन जल उपयोग कानून के प्रावधानों पर भी चर्चा की।

इसके अतिरिक्त, जापानी पक्ष ने जकार्ता, इंडोनेशिया में भूमि धंसाव पर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना के निष्कर्षों को प्रदर्शित किया, जिसमें जापान-इंडोनेशिया सहयोग गतिविधि के तहत किए गए रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डाला गया।

## परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

### पोलावरम सिंचाई परियोजना

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुउद्देशीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता बनाने के लिए एक मृदा-शैल बांध (ईसीआरएफ) के साथ-साथ काठी-मृदा बांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंग, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 960 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन, 540 गांवों में पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए नियुक्त किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों का मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए गठित समिति की चौथी बैठक 13.05.2024 को श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) की अध्यक्षता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (के.ज.आ) की सह-अध्यक्षता में सीईओ, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए),

सेवा भवन, नई दिल्ली में- हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) की स्थिति की समीक्षा के लिए 21.05.2024 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसपीआर विंग और केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) के अधिकारियों ने भाग लिया।

अतिरिक्त भुगतान के संबंध में पीपीए द्वारा प्रदान किए जाने वाले विवरण की स्थिति, सलाहकार और एजेंसी को काम पर रखने की स्थिति और पीपीए के कार्यालय के स्थानांतरण के मुद्दों पर चर्चा हुई।

### लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 14.05.2024 को के.ज.आ (मुख्यालय), सेवा भवन, नई दिल्ली में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में के.ज.आ, यूजेवीएनएल, जीएसआई, एलएंडटी के अधिकारियों और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) के सदस्यों ने भाग लिया।

## साइटों/परियोजनाओं का दौरा

### खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स टेलिंग बांध, खेतड़ी, राजस्थान

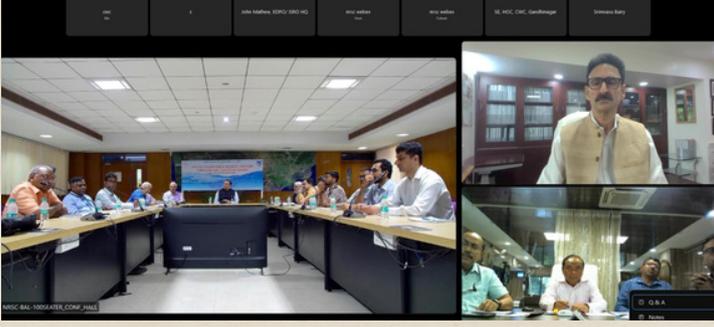
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में टेलिंग बांध की ऊंचाई ईएल 406 मीटर से ईएल 413 मीटर तक बढ़ाने के लिए निर्माण चरण के आरेखण की तैयारी और डिजाइन परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

केंद्रीय जल आयोग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों की एक टीम ने टेलिंग बांध की वर्तमान ऊंचाई ईएल 406 मीटर से ईएल 413 मीटर तक बढ़ाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए 03.05.2024 को साइट का एक संयुक्त दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना और प्रस्तावित ऊंचाई

वृद्धि के लिए डिजाइन परामर्श प्रदान करने के लिए बांध की मौजूदा स्थितियों का मूल्यांकन करना था।



## गोदावरी और तापी नदी घाटियों के लिए स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली



केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने एनआरएससी, हैदराबाद द्वारा आयोजित "गोदावरी और तापी नदी बेसिन के लिए स्थानिक बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली" पर 06-10 मई 2024 तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सत्र में के.ज.आ, एनआरएससी, इसरो, मेघालय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, के.ज.आ ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली कुशल और सक्रिय आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने के.ज.आ द्वारा हाल ही में शुरू की गई बाढ़ मॉडलिंग की पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हिमनद झील विस्फोट के कारण बाढ़ (जीएलओएफ), शहरी बाढ़ आदि जैसे नए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मॉडलिंग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी को सिस्टम के वास्तविक समय संचालन और बाढ़ मॉडल की तकनीकी जानकारी सीखने में मदद मिलेगी और यह आने वाले लंबे समय तक बहुत उपयोगी होगा जब हम अन्य बेसिनों में बाढ़ के पूर्वानुमान का विस्तार करेंगे।

## ट्रॉयज़, फ्रांस में एडीसीपी रेगाटा

केंद्रीय जल आयोग के 4 अधिकारियों नामतः श्री अंकित डुडेजा, ईईई; श्री निशांत कुमार, ईईई; श्री विपुल कुमार वर्मा, एईई और श्री भरत, एडी-॥ की एक टीम ने ट्रॉयज़, फ्रांस में 2024 एडीसीपी रेगाटा में भाग लिया।

एडीसीपी और अन्य डिस्चार्ज माप तकनीकों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 2013 से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष, यह कार्यक्रम ईपीटीबी ग्रैंड्स लैक्स डी सीन और फ्रांस के गुप डॉपलर हाइड्रोमेट्री द्वारा आयोजित किया गया था। अंतर-प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम 22 मई और 23 मई, 2024 को लेक ओरिएंट के अनुप्रवाह में, ट्रॉयज़ के पास, मेसनिल सेंट-पेरे के कम्यून में आयोजित किया गया था। डिस्चार्ज की विभिन्न स्थितियों जैसे वेग, गहराई, क्रॉस-सेक्शन और वॉल्यूम में अलग-अलग तकनीकों जैसे मोबाइल एडीसीपी, स्थिर एडीसीपी, वैडिंगरोड्स पर वर्तमान मीटर (किसी भी प्रकार) और ट्रेसरडिल्यूशन (नमक, रोडामाइन, यूरेनिन) का उपयोग करके डिस्चार्ज अवलोकन किए गए थे।

रेगाटा के लिए, आयोजकों द्वारा "कैनल डी मोर्ज" पर कुल 50 खंड तैयार किए गए थे। विभिन्न देशों की टीमों को खंड आवंटित किए गए थे और प्रत्येक टीम ने 12 बार अपने उपकरण का उपयोग करके डिस्चार्ज एकत्र किया था।

भारतीय टीम ने 1सोनटेक एम9 एडीसीपी; एक कप टाइप (वर्टिकल एक्सिस) करंट मीटर और एक पिग्मी करंट मीटर की मदद से अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत में अपनाए जा रहे तरीकों के साथ-साथ हाइड्रोलॉजिकल उपकरणों और यंत्रों को प्रदर्शित करने के लिए उपकरण भारत से ले लाए गए थे। भारतीय टीम ने रासायनिक ट्रेसर कमजोर पड़ने की विधि, मोटर और रिमोट से संचालित एडीसीपी आदि जैसे अन्य तरीकों का उपयोग करके हाइड्रोमेट्रिक अवलोकन में भी भाग लिया।

विस्तृत परिणाम तुलना और अनिश्चितता विश्लेषण के लिए एडीसीपी, वर्तमान मीटर और अन्य तरीकों से प्राप्त डिस्चार्ज परिणाम आयोजकों के साथ साझा किए गए हैं।



## I. बाढ़ से संबंधित मामले

### देश में बाढ़ की स्थिति - मई 2024

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 मई 2024 की अवधि के दौरान, कुल 55 (53 स्तर + 2 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 48 (47 स्तर + 1 प्रवाह) पूर्वानुमान 87.27% सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मई माह के दौरान कोई रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी नहीं किए गए केवल 28 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

22 मई 2024 से 29 मई 2024 की अवधि के दौरान, गंभीर चक्रवाती तूफान "रेमल" पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पार कर गया था। इस अवधि के दौरान केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के लिए विशेष परामर्श जारी किए गए।

### 01.05.2023 से 31.05.2024 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

#### चरम बाढ़ की स्थिति

इस अवधि के दौरान किसी भी बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति नहीं देखी गई।

किसी भी बाढ़ निगरानी स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति नहीं देखी गई।

#### गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम में 5 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, मणिपुर, केरल और त्रिपुरा में 11 निगरानी स्टेशन पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

### सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

### सीमा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

तमिलनाडु में 1 जलाशय में उसकी सीमा से अधिक प्रवाह प्राप्त हुआ।



## 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य में व्यापक बाढ़ के मद्देनजर संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की तीसरी बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में व्यापक बाढ़ को ध्यान में रखते हुए 14 मई, 2024 को संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए समिति की तीसरी बैठक आयोजित की।

विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष, के.ज.आ ने उल्लेख किया कि अधिकांश टीओआर पर काम पूरा हो चुका है और समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक में के.ज.आ, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर, हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब और उत्तराखंड, सीडब्ल्यूपीआरएस, आईएमडी, एनआरएससी, एनडब्ल्यूआईसी, एसजेवीएनएल, एचपीपीसीएल, एचपी और उत्तराखंड के एसडीएमए, एचपी के जलशक्ति विभाग आदि के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, अब तक हुई प्रगति और सभी संगठनों के हाइड्रोलॉजिकल डेटा के एकीकरण, राज्यों में नए एचओ साइट खोलने, पोंग और भाखड़ा बांधों के नियम वक्रों के विकास से संबंधित मुद्दों पर



## II. अंतर-राज्य विवाद

### पेन्नैयार नदी जल विवाद



पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की चौथी बैठक 22.05.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई और चार सह-बेसिन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनआईएच रूडकी और सीजीडब्ल्यूबी के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

सह-बेसिन राज्यों के प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्यों ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के मुद्दे पर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये। विचार-विमर्श के बाद, बैठक में लिए गए निर्णयों में सीजीडब्ल्यूबी और सी एंड एसआरओ, के.ज.आ द्वारा डेटा का विश्लेषण करना, फील्ड विजिट का अस्थायी कार्यक्रम, सह-बेसिन राज्यों के साथ राज्य के डेटा को साझा करना और तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य द्वारा 2-3 दिनों के भीतर अन्य अपेक्षित डेटा/जानकारी प्रस्तुत करना शामिल है।

## III. अन्य गतिविधियाँ

### केंद्रीय जल आयोग एवं सूरत नगर निगम तथा उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन

15 मई, 2024 को के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की उपस्थिति में दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

तापी नदी पर पारंपरिक बैराज के निर्माण के लिए एसएमसी को के.ज.आ द्वारा समीक्षा डिजाइन परामर्श कार्य प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और सूरत नगर निगम (एसएमसी), गुजरात के

बीच पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक, बीसीडी (एनडब्ल्यू एंड एस), के.ज.आ और उप नगर आयुक्त, एसएमसी, गुजरात ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (यूपीडीसीसी) लिमिटेड, उत्तराखंड के बीच दूसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन यूपीडीसीसी को जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए समीक्षा डिजाइन परामर्श कार्य प्रदान करने के लिए किया गया था जिसमें सिंचाई, बिजली और पीने के पानी के लिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गोला नदी पर 150.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध सहित जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करना शामिल था। निदेशक, सीएमडीडी (ई एंड एनई), के.ज.आ और महाप्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), जमरानी यूपीडीसीसी लिमिटेड, उत्तराखंड ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सूरत नगर निगम की परियोजना का उद्देश्य सिंगनपोर में बंध-सह-सेतू से अतिरिक्त पानी का संरक्षण करना, सूरत शहर और उसके परिवेश की दीर्घकालिक जल आपूर्ति आवश्यकताओं को उजागर करना, बंध-सह-सेतू के अनुप्रवाह में तापी नदी में ज्वारीय गाद एवं प्रदूषण तथा अडाजण, अठवा और उमरा जैसे आस-पास के क्षेत्रों में लवणता को प्रवेश करने से रोकना था। इसके अतिरिक्त, परियोजना को मीठे पानी के भंडार बनाकर भूजल पुनर्भरण की सुविधा और भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ, के.ज.आ बैराज और इसकी स्पष्ट संरचना के निर्माण के लिए समीक्षा डिजाइन परामर्श कार्य प्रदान करने पर सहमत हो गया है।

जमरानी बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले चार जिलों के 57065 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करने का प्रावधान है; वर्ष 2051 के लिए अनुमानित हल्द्वानी शहर की 10.65 लाख की अनुमानित आबादी के लिए सालाना 42.70 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराना और 14 मेगावाट डैम टो हाइड्रोपावर प्लांट की स्थापना से सालाना 63.4 एमयू जलविद्युत का उत्पादन करना। परियोजना को अक्टूबर 2022 में भारत सरकार की आर्थिक कार्य कैबिनेट समिति द्वारा पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत मंजूरी मिल गई है।



## भूकंपीय डिजाइन मापदंडों के मूल्यांकन के लिए के.ज.आ के एनसीएसडीपी दिशानिर्देशों में संशोधन

श्री संजयकुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 08.05.2024 को अपनेकक्ष में "साइट-विशिष्ट भूकंपीय डिजाइनमापदंडों के आकलन के लिए के.ज.आके एनसीएसडीपी दिशानिर्देशों के प्रस्तावित संशोधन" के संबंधमें बैठककी अध्यक्षता की। बैठक में डिजाइनइकाइयों और एफईएंड एसएनिदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया। एनसीएसडीपी दिशानिर्देश के लिएप्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिमरूप दिया गया।

## गंगा-पद्मा नदी से उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए गठित समिति की पांचवीं बैठक



केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्म नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने हेतु एक एकीकृत योजना तैयार करने व संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए 16 मई 2024 को समिति की 5वीं बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की।

बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जीएफसीसी, एफबीपी, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनआरएससी, आईडब्ल्यूआई, बिहार सरकार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया।

समिति के निर्देशानुसार सलाहकार द्वारा विकसित 1डी एवं 2डी मॉडल की समीक्षा की गई। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद के.ज.आ अध्यक्ष ने इच्छा जताई कि के.ज.आ, सीडब्ल्यूपीआरएस, सलाहकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों की टीम एक सप्ताह के भीतर बचे हुए मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। उन्होंने निर्देश दिया कि फरक्का बैराज के अनुप्रवाह में निर्माणाधीन पुल को भी मॉडल में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार अपेक्षित डेटा प्रदान करके सलाहकार की मदद करेगी। इसके बाद समिति रिपोर्ट को जल्द अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्र का दौरा करेगी।

## विश्व बैंक द्वारा समर्थित सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की प्रगति पर चर्चा

10.05.2024 को, विश्व बैंक द्वारा समर्थित सिंचाई प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की प्रगति पर चर्चा करने के लिए सचिव, जल संसाधन विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एक हाइब्रिड बैठक की गई। के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव सहित जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागके वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्व बैंक की टीम और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया। के.ज.आ के मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ) श्री पद्मा दोर्जे ग्याम्बा ने सामान्य उपकरण और योजना-स्तरीय मूल्यांकन के लिए समयसीमा पर एक प्रस्तुति दी। विश्व बैंक के प्रोफेसर पूलड करीमी ने सिंचाई और फसल प्रदर्शन, कार्यक्षमता, डेटा स्रोतों और प्रमुख संकेतकों के उपकरण के व्यापक दृष्टिकोण का विस्तृत अवलोकन प्रदान किया।

अध्यक्ष, के.ज.आ ने मूल्यांकन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सटीक स्कोरिंग, क्षेत्र सत्यापन और राज्यों के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। आयुक्त एसपीआर ने संकेतकों की परस्पर जुड़ी प्रकृति और एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सचिव, जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने उपकरण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संकेतकों की संख्या को सुव्यवस्थित करने और कृषि सचिव के साथ सहयोग करने का सुझाव दिया।

## जल निकाय प्रबोधन ऐप

स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एसएसी), इसरो अहमदाबाद के सहयोग से, ग्रीन गुड लैब्स (जीजीएल) द्वारा विकसित जल निकाय प्रबोधन ऐप को समय पर और सटीक डेटा संग्रह के माध्यम से जल प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐप लगभग 5000 प्रमुख और 2.4 मिलियन समग्र जल निकायों की निगरानी करता है, जो 7 से 12 दिन की आवृत्ति पर सतही क्षेत्र डेटा प्रदान करता है। इस बीच, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा जल निकाय सूचना प्रणाली (डब्ल्यूबीआईएस) पोर्टल लगभग 1.6 मिलियन जल निकायों (0.25 हेक्टेयर और ऊपर) की निगरानी करता है, जो 1 हेक्टेयर और उससे अधिक के जल प्रसार क्षेत्रों पर जोर देता है।



श्री कुश्विंदर वोहरा अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार ने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जल निकायों की निगरानी हेतु ऐप्स की समीक्षा करने के लिए 21.05.2024 को एक बैठक आयोजित की।

ग्रीनगुड लैब्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एसएसी), इसरो द्वारा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जल निकायों की निगरानी के लिए अपने ऐप के माध्यम से 10 जलाशयों के विश्लेषण के संबंध में प्रस्तुतियां दी गईं।

के.ज.आ के अध्यक्ष ने इन ऐप्स के विकास के लिए एसएसी और ग्रीनगुड लैब्स द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जल निकाय में पानी की विशिष्ट मात्रा संग्रहित करने के साथ उपयुक्त निर्णय समर्थन प्रणाली को शामिल करने पर जोर दिया, जिससे पंचायतों, नगर पालिकाओं, किसान समूहों और परियोजना प्रबंधकों सहित हितधारकों को मूल्यवान जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए ऐतिहासिक डेटा सहित जल निकायों के लिए क्षेत्र-क्षमता-ऊंचाई वक्र उत्पन्न करने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा ऐप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अध्यक्ष, के.ज.आ ने जल संसाधनों के क्षेत्र में विकसित प्रौद्योगिकियों में निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि एजेंसियों के बीच सहयोग देश में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

## आईसीआईडी की दीर्घकालिक वित्तीय और तकनीकी स्थिरता पर कार्यबल की दूसरी बैठक

सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICID) 1950 में स्थापित एक अग्रणी वैज्ञानिक, तकनीकी और पेशेवर गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्थिर कृषि जल प्रबंधन को बढ़ावा देने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग में स्थित भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी), अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास (आईसीआईडी) के लिए भारत की प्रतिनिधि राष्ट्रीय समिति है। अध्यक्ष, के.ज.आ आईएनसीआईडी के अध्यक्ष हैं, सीई (ईएमओ) के.ज.आ इसके सदस्य-सचिव हैं, और रिमोटसेंसिंग निदेशालय, के.ज.आ आईएनसीआईडी सचिवालय के रूप में कार्यरत हैं।

दीर्घकालिक वित्तीय और तकनीकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर 2023 को विजाग, भारत में आयोजित 74वीं

अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईसीआईडी) की बैठक के दौरान आईसीआईडी (टीएफटी और एफएस) की दीर्घकालिक वित्तीय और तकनीकी स्थिरता पर टास्क फोर्स की स्थापना संकल्प आईसीआईडी-1/74 के तहत की गई थी।

अध्यक्ष, के.ज.आ/आईएनसीआईडी, ने 14 मई 2024 को आयोजित आईसीआईडी (टीएफटी-टी एंड एफएस) की दीर्घकालिक वित्तीय और तकनीकी स्थिरता पर टास्क फोर्स की दूसरी बैठक में भाग लिया। बैठकों के दौरान, आय और व्यय की कमजोरियों की जांच करने, नए आय मॉडल का प्रस्ताव करने और पंजीकरण शुल्क, आयोजक दायित्वों, प्रायोजन भुगतान और जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन सहित आईसीआईडी-ब्रांडेड घटनाओं की वित्तीय संरचना की समीक्षा करने पर चर्चा की गई। एजेंडे में आयोजनों से आईसीआईडी के राजस्व हिस्से को भी शामिल किया गया, वित्तीय प्रभाव के लिए वार्षिक आईसीआईडी कार्यक्रमों की अवधि की समीक्षा की गई, सदस्यता शुल्क गणना विधियों को संशोधित किया गया और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए सदस्यता संरचना को बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य विषयों और तकनीकी संवाद क्षेत्रों के दायरे का विस्तार करके सदस्यों के लिए आईसीआईडी के तकनीकी मूल्य को बढ़ाना है।

## हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मजबूत करना (एससीए-हिमालय)-ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग फ्रेमवर्क का मसौदा

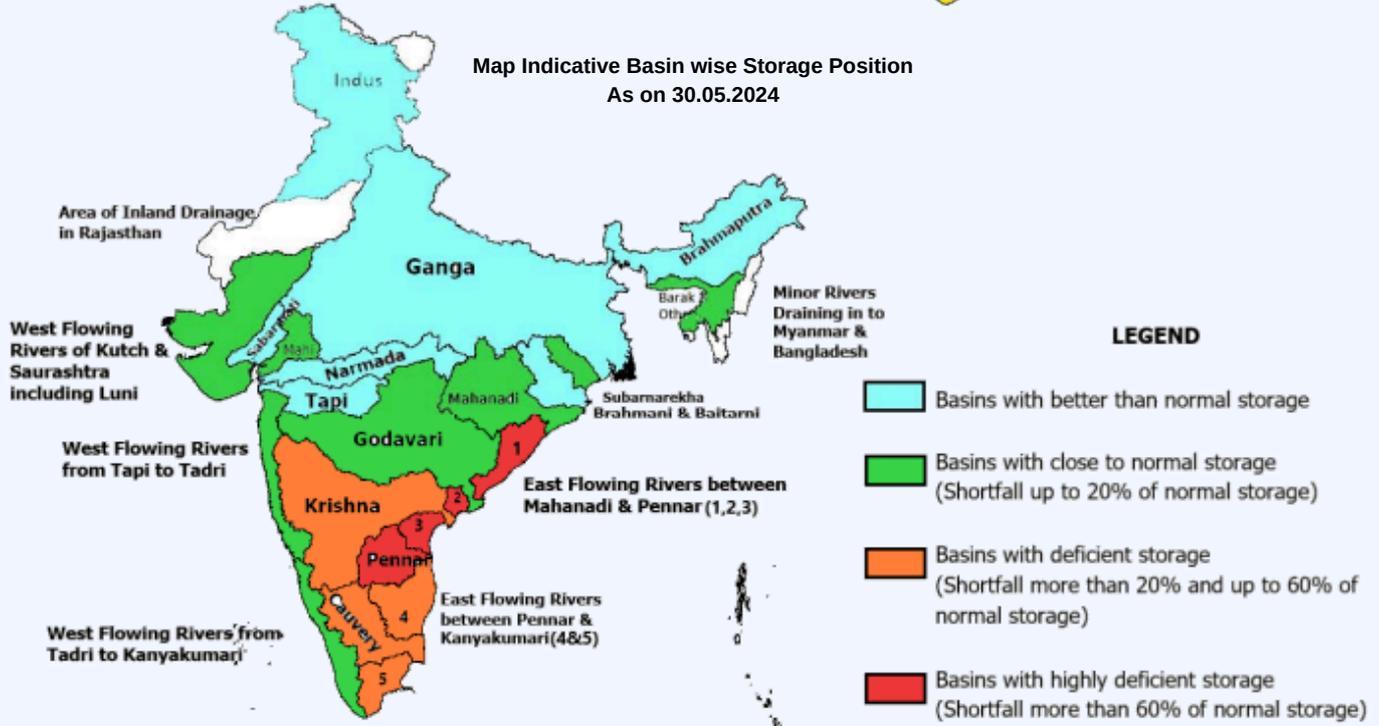
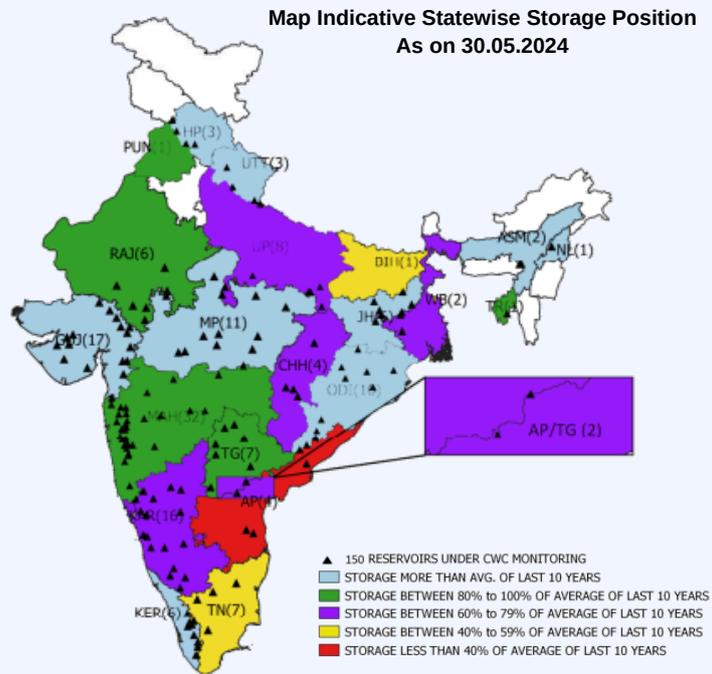
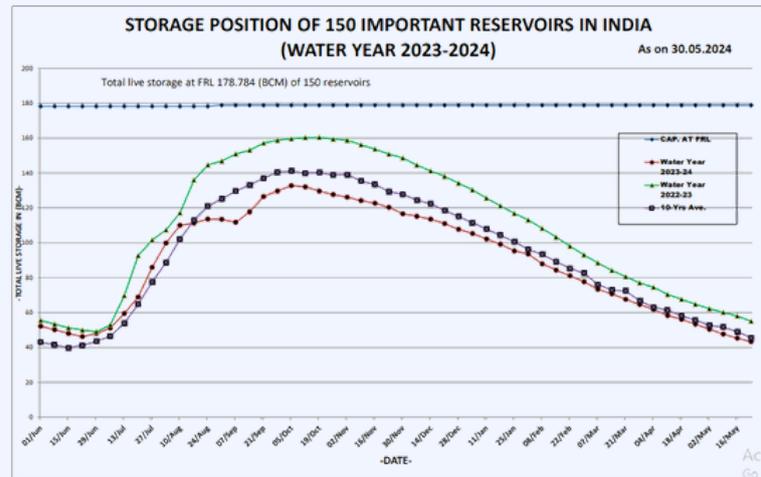
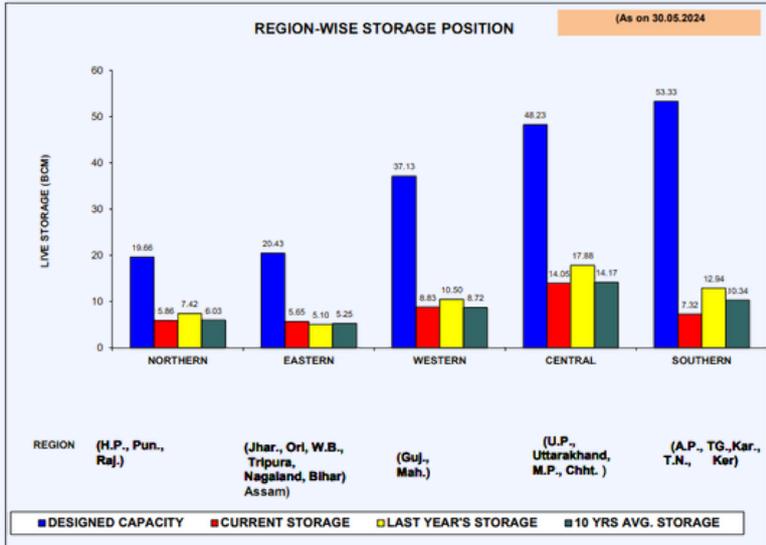
भारत में विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी (एसडीसी) "हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मजबूत करना (एससीए-हिमालय)" परियोजना के माध्यम से भारतीय हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पहल के कार्यान्वयन का समर्थन कर रही है। इस भारत-स्विट्जरलैंड सहयोग का उद्देश्य संबंधित राज्य सरकार के विभागों की क्षमताओं को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले जलवायु कार्यों को बढ़ावा देना है। यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना के हिस्से के रूप में, ग्लेशियो-हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग पर एक मसौदा ढांचा विकसित किया गया है। 03.05.2024 को, "भारत के हिमानीकृत (ग्लेशियरीकृत) और गैर-हिमानीकृत (गैर-ग्लेशियरीकृत) दोनों क्षेत्रों में जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने की रूपरेखा" पर चर्चा हेतु केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान, सुबनसिरी उप-बेसिन पर जल विज्ञान (एनई) निदेशालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष, के.ज.आ ने निर्देश दिया कि इस परीक्षण अध्ययन पर के.ज.आ को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एससीए-हिमालय टीम से परामर्श लिया जाएगा।

## IV. जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 30.05.2024 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 41.705 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 23% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 53.832 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 44.511 बीसीएम था। इस प्रकार, 30.05.2024 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 77% और पिछले दस वर्षों के औसत स्टोरेज का 94% है।





माही तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, गांधीनगर को कार्यालय श्रेणी में नराकास राजभाषा शील्ड, वर्ष 2023-24 का द्वितीय स्थान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नराकास की पत्रिका "गांधीनगरी" के पहले अंक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ आलेख श्रेणी में "नदी-जोड़ योजना की आवश्यकता"- आलेख के लिए श्री दत्त कुमार सोपान चासकर, मुख्य अभियंता को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।



ओडिशा



कर्नाटक



गोवा

राज्यों और हितधारकों के साथ 2024-25 के लिए पहली त्रैमासिक वार्ता।

बाढ़ की भविष्यवाणी करने और स्थानीय प्रशासन को समय पर जानकारी देने के लिए, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की तैयारियों के समन्वय के लिए मानसून की शुरुआत से पहले संबंधित राज्यों और हितधारकों के साथ बैठकें कीं।



यमुना बेसिन संगठन



उत्तराखंड



गुजरात



ओडिशा



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध  
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री पदमा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
ई-मेल: media-cwc@gov.in